

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] No. 125] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सा.का.नि.153(अ).-केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 352ख के साथ पठित धारा 352चक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा) संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 3 के उपनियम (1) में,-
- (क) खंड (क) में,-
 - (अ) उपखंड (i) में, "दो लाख यूनिट", शब्दों के स्थान पर "30.2 लाख यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
 - (आ) उपखंड (ii) में,
 - (अ) मद (अ) में, "आठ सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "1208 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
 - (आ) मद (आ) में, "छः सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "906 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
 - (इ) मद (इ) में, "चार सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "604 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
- (ख) खंड (ख) में,-
 - (अ) उपखंड (i) में, "दस लाख", शब्दों के स्थान पर "15.1 लाख यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

969 GI/2017 (1)

(आ) उपखंड (ii) में,-

- (अ) मद (अ) में "चार सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "604 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
- (आ) मद (आ) में, "तीन सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "453 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;
- (इ) मद (इ) में, "दो सौ यूनिट", शब्दों के स्थान पर "302 यूनिट", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा ।

[फा.सं. एस आर-12011/2/2016-एमजी]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

टिप्पण: – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 98(अ) द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2015 को प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF SHIPPING NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

- **G.S.R.153** (E).—In exercise of the powers conferred by section 352FA read with section 352B of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2015 namely:-
- 1. **Short title and Commencement.** (1)These rules may be called the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2015 (herein referred to as the principal rules), in rule 3, in sub-rule (1),-
 - (a) in clause (a),
 - (A) in sub-clause (i), for the words "two million units", the figures and words "3.02 million units", shall be substituted;
 - (B) in sub-clause (ii),
 - (a) in item (A), for the words, "eight hundred units", the figures and words "1208 units", shall be substituted:
 - (b) in item (B), for the words, "six hundred units", the figures and words "906 units", shall be substituted;
 - (c) in item (C), for the words, "four hundred units", the figures and words "604 units", shall be substituted;
 - (b) In clause (b),-
 - (A) in sub-clause (i), for the words, "one million", the figures and words "1.51 million units", shall be substituted;
 - (B) in sub-clause (ii), -
 - (a) in item (A), for the words, "four hundred units", the figures and words "604 units", shall be substituted;
 - (b) in item (B), for the words, "three hundred units", the figures and words "453 units", shall be substituted;
 - (c) in item (C), for the words "two hundred units", the figures and words "302 units", shall be substituted.

[F. No.SR-12011/2/2016-MG]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 98(E), dated the 16th February, 2015.